THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) Silkwaste is classified as a free item in the Import-Export Policy. Exports of silkwaste from India in 1997-98 (Prov.) were 1600 tonnes, out of which 53 tonnes were exported to China & 304 tonnes to Hong Kong. The average FOB price of the undegummed silkwaste per kg. was of the order of $ 4.6 in April 1997 and has touched about $ 7 now. The import of silkwaste was of the order of 116 tonnes (carded or combed is 99 tonnes and not carded or combed is 17 tonnes) with an average price per kg. of about $ 13.6 (carded or combed) and $ 4.7 (not carded or combed) respectively in the year 1997-98. Out of this the import of silkwaste from China was 107 tonnes. Based on the above data, it would be difficult to conclude that China has started an unscrupulous business in silkwaste trade with India.

(b) Does not arise.

(c) The Government keeps close watch on the situation and as and when situation warrants, necessary remedial measures will be taken.

Silkwaste by Spun Silk Factories

1642. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the number of spun silk factories consuming silkwaste in the country;

(b) what is their production capacity;

(c) the quantity of silkwaste used by these factories;

(d) what is the export value of the produce; and

(e) what is the value addition?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) The number of organised spun silk mills in the country are 20 including one EOU which has recently gone into production.

(b) Their installed production capacity is 46480 spindles for spun silk yarn and 7450 spindles for noil yarn.

(c) The annual consumption of silkwaste by these units generally ranges between 2500 to 3500 tonnes. During 1997-98 (April—February) the actual consumption was 2465 tonnes.

(d) Exports are of mostly of silkwaste and silk carpets. Average export value of silkwaste and carpets for the year 1997-98 are Rs. 200 per Kg. and Rs. 8544 per sq. meter respectively.

(e) The value of a carpet as of now is about three times the cost of the silkwaste input. In the case of spun silk yarn because of the current high silk waste prices, the value addition is negligible.

New Textile Policy

1643. SHRI GHUFRAN AZAM:
SHRI JANARDHANA POOJARY:
SHRI PRANAB MUKHERJEE:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government propose to formulate an expert group to give a fresh look on the textile policy;

(b) whether Government have set up any expert group for the purpose;

(c) if so, the details of changes Government propose in the policy; and

(d) by when the new policy would be announced and implemented?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) to (d) It has been decided to set up expert group under the Chairmanship of Shri S.R. Sathyam for the purpose of enabling the formulation of a new textile policy. The composition and the terms of reference are under finalization.

रेशम उत्पादन हेतु जापान की सहायता

1644. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रेशम उत्पादन के विकास हेतु जापान द्वारा स्वीकृत परियोजना की लागत कितनी है;

(ख) यह स्वीकृति किस तिथि को दी गई तथा उन जिलों के नाम क्या हैं, जहां यह परियोजना कार्यान्वित की जानी है;

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत रेशम उत्पादन का विकास संबंधी कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) परियोजना की लागत 109.98 करोड़ रुपये है।

(ख) दिसम्बर, 1997 में स्वीकृति दी गई थी और इस परियोजना में बिलासपुर, रायगढ़ और सुरगुजा के जिलों में तसर रेशम उत्पादन शामिल है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

(घ) परियोजना में 4000 हैक्टेयर क्षेत्र में तसर का रोपण करने, रोपन बढ़ाने के लिए मुख्य रेशम उत्पादन समितियों का गठन करने, रेशम कीट और रिलींग कोसों का पालन करने, 14 अनाज भण्डारों, 4 पीठ केन्द्रों, 1 पीठ केन्द्र, 30 ग्रामीण स्तर के भण्डारण केन्द्रों, 3 जिला स्तरीय कौसा गोदामों, 1 क्षेत्र स्तरीय अनुसंधान व प्रशिक्षण केन्द्र, 20 रीलरों की प्रत्येक क्षमता वाले 2 रिलींग केन्द्रों तथा परियोजना के क्रियान्वयन और मानीटरिंग के लिए परियोजना कार्यालय की स्थापना करने का प्रावधान है। इनके अतिरिक्त परियोजना में उसके सफल क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने और परियोजना के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। ऐसी आशा है कि परियोजना के पूरा होने के बाद प्रतिवर्ष 75 मिलियन टन तसर रेशम और 22.5 मिलियन टन तसर स्पन यार्न का उत्पादन होने के साथ-साथ 10,000 व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त होगा।

कार्पेट टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट द्वारा कार्य प्रारंभ न किया जाना

1645. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भदोही, उत्तर प्रदेश में "कार्पेट टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट" की स्थापना हेतु वर्ष 1993 में एक प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने इस संस्थान के लिए 10 एकड़ भूमि भी उपलब्ध कराई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय ने इस संस्थान के लिए कुछ पदों के सृजन के बारे में वर्ष 1996 में सूचना दी थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संस्थान द्वारा कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है जबकि इससे संबंधित प्रस्ताव पिछले दो दशकों से विचाराधीन हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा : (क) जी नहीं।

(ख) राज्य सरकार ने संस्थान के लिए 4.25 एकड़ का प्लाट उपलब्ध कराया है।

(ग) वर्ष 1996 में, उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस संस्थान के लिए पदों के सृजन के एक प्रस्ताव के सम्बंध में सूचित किया था।

(घ) भवन का निर्माण और आधारभूत सुविधाओं आदि प्रदान करने का कार्य पूर्ण हो गया है। इस समय परियोजना संशोधित लागत अंकलन का अनुमोदन और संयंत्र व उपकरणों आदि की खरीद और संस्थान प्रगति पर है तथा परियोजना की समाप्ति को जल्द पूरा किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के दस्तकारों के लिए कार्यशाला

1646. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 1000 दस्तकारों के लिए एक कार्यशाला (आवासीय) हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार द्वारा 2500 दस्तकारों के लिए कार्यशाला- सहित-आवास हेतु भी एक प्रस्ताव भेजा गया था;

(ग) क्या यह सच है कि इस परियोजना की 5.35 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण अनुदान राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (घ) जी हां। उत्तर प्रदेश सरकार से 5.35 करोड़ रुपये की विवज्ञा के दो प्रस्ताव एक 1000 कारीगरों के लिए वर्कशैड तथा दूसरा 2500 कारीगरों के लिए वर्कशेड-सह-आवास प्राप्त हुए हैं।